भारतीय कंपनियों का नया ठिकाना दुबई

85,841 भारतीय कंपनियां पंजीकृत, छह महीने में 7,579 का इजाफा

1 60.6 अरब डॉलर पहुंचा भारत-दुबई गैर-तेल व्यापार

2 8.8 अरब डॉलर निवेश भारत से दुबई में आया

3 9.3 अरब डॉलर दुबई की कंपनियों ने भारत में लगाया

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुबई भारतीय कंपनियों को मध्य पूर्व, आधिका और से ईएम अन्य वैश्विक बाजारों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराता है. विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, उत्कृष्ट संपर्क व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल और निवेशकों व 5जी ग्राहकों तक सीधी पहुंच इसकी प्रमुख विशेषताएं है.

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 30 अगस्त व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. दुबई चेंबर्स के अध्यक्ष मोहम्मद अली राशिद लूता ने बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 के अंत तक दुबई चैंबर के सक्रिय सदस्यों के रूप में पंजीकृत भारतीय कंपनियों की संख्या बढ़कर 85,841 हो गई है.

वर्ष 2026 की पहली छमाही के दौरान ही 7,579 नई भारतीय कंपनियां दुबई चैंबर से जुड़ीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. दुबई आधारित प्रकाशन अरेबियन बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंधों में लगातार विस्तार देखा जा रहा है. लुता ने बताया कि वर्ष 2025 में भारत और दुबई के बीच गैर-तेल व्यापार 60.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2025 के बीच दुबई ने भारत से लगभग 8.8 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया, जिनमें से केवल वर्ष 2025 में ही 2.3 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) दर्ज किया गया, जो भारतीय कंपनियों के बढ़ते वैश्विक विस्तार और दुबई पर उनके भरोसे को दर्शाता है.निवेश केवल एक दिशा में नहीं हुआ, बल्कि दुबई की कंपनियों ने भी भारत में निवेश किया है. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 से 2025 के बीच दुबई की कंपनियों ने भारत में 147 परियोजनाओं के माध्यम से 9.3 अरब डॉलर का निवेश किया.

चीनी 294 रु. महंगी सरसों तेल 162 रु. चढ़ा

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 30 अगस्त घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चीनी 294 रुपये और सरसों तेल 162 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो गया. चावल, अधिकतर खाद्य तेल और दालों में भी तेजी रही.

बीते सप्ताह मीठे के बाजार में गुड़ का औसत भाव 294 रुपये चढ़कर सप्ताहांत पर 5,911 रुपये प्रति क्विंटल रहा. इसमें पहले तीन दिन तेजी देखी गयी जबकि अंतिम तीन दिन कीमतों में उतार देखा गया. इससे पहले के सप्ताह में चीनी 777 रुपये महंगी हुई थी.

गुड़ का भाव पिछले सप्ताह 310 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया. यह एक सप्ताह पहले 323 रुपये महंगा हुआ था. सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 31 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 4,134 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 29 रुपये महंगा हुआ और 2,867 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया. आटे का भाव भी 15 रुपये चढ़कर 3,325 रुपये प्रति क्विंटल हो गया.

सप्ताह के दौरान उड़द दाल की औसत कीमत 44 रुपये और तुअर दाल की 35 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी. मूंग दाल 19 रुपये और चना दाल 17 रुपये महंगी हुई.

ईएमएफ सीमा हुई दोगुनी अब नेटवर्क विस्तार आसान

- 5 से बढ़कर 10 वॉट/वर्ग मीटर हुई सीमा
- एक टॉवर से बड़े क्षेत्र में कर सकेंगे कवरेज
- टेलीकॉम कंपनियों की लागत घटने की उम्मीद

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 30 अगस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की निर्धारित सीमा में ढील देने का फैसला किया है. इसका रिपोर्ट के अनुसार, नए नियम अगले महीने से लागू होंगे.

नई व्यवस्था के तहत 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन के लिए अनुमत पावर - डेसिटी को मौजूदा 5 वाट प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 10 वाट प्रति वर्ग मीटर किया जाएगा. इस बदलाव से टेलीकॉम कंपनियों एक ही टावर से ज्यादा बड़े क्षेत्र में नेटवर्क कवरेज दे सकेंगी. इससे भविष्य में नए टावर लगाने की जरूरत कम हो सकती है और नेटवर्क विस्तार की लागत भी घट सकती है. टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से ईएमएफ सीमा बढ़ाने की मांग कर रही थीं. उनका कहना था कि मौजूदा सीमा 5जी नेटवर्क को प्रभावी ढंग से फैलाने में बाधा बन रही थी. भारत कई वर्षों से इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आइयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन द्वारा सुझाई गई सीमा की तुलना में अधिक सख्त रेडिएशन मानक अपनाता रहा है. आईसीएनआईआरपी ईएमएफ के स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी प्रभावों को लेकर दिशानिर्देश देता है और इसके मानकों का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में किया जाता है. भारत में पहले पावर डेंसिटी की सीमा 1 वाट/वर्ग मीटर थी. इसे पिछले साल बढ़ाकर 5 वाट/वर्ग मीटर किया गया था. अब इसे बढ़ाकर 10 वाट/वर्ग मीटर किया जा रहा है.

कम साइटों से ही बढ़ता जा रहा नेटवर्क कवरेज

ऊंची सीमा से टेलीकॉम ऑपरेटर एक टावर से बड़े क्षेत्र को कवर कर सकेंगे. इससे नेटवर्क विस्तार के लिए आवश्यक साइटों की संख्या कम हो सकती है और कंपनियों की लागत घट सकती है. इसका सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को होने की संभावना है, क्योंकि कंपनी अभी अपने 5जी नेटवर्क का विस्तार कर रही है. वह अब अधिक सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने नेटवर्क की योजना बना सकती है. वहीं भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, जो पहले ही बड़े पैमाने पर 5जी नेटवर्क तैनात कर चुके हैं, उन्हें भी मौजूदा साइटों के अधिक कुशल इस्तेमाल और भविष्य में कम अतिरिक्त पूंजीगत खर्च का फायदा मिल सकता है. नई 10 वाट प्रति वर्ग मीटर की सीमा लगभग 137 देशों में अपनाए गए मानकों के अनुरूप बताई जा रही है.

शेयर स्वैप समेत तीन विकल्पों पर मंथन की तैयारी

टाटा संस में हिस्सेदारी बेचेगा एसपी समूह

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 30 अगस्त टाटा समूह और शापूरजी पल्लोनजी समूह के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है. दोनों पक्ष टाटा संस में एसपी समूह की 18.4% हिस्सेदारी को लेकर कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक इनमें टाटा की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों के बदले टाटा संस की हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव भी शामिल है।टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं. दरअसल, एसपी समूह पर भारी कर्ज है. उनके हाथों में टाटा समूह का पहला बड़ा कर्ज भुगतान जुलाई 2028 में होना है, जिसकी वजह से अगले 18 महीनों में बड़े समाधान की उम्मीद की जा रही है.

एवरेस्ट की हींग पर एफएसएसएआई का प्रतिबंध

कम्पाउंडेड हींग के सैंपल जांच में फेल

लालजी गोधू की हींग पर भी कार्रवाई

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 30 अगस्त भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मसाला कंपनी एवरेस्ट और लालजी गोधू के कम्पाउंडेड हींग प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

जांच में दोनों कंपनियों की हींग के सैंपल तय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सिर्फ हींग उत्पादों पर लागू है. एवरेस्ट और लालजी गोधू के अंडा करी मसाला, चिकन करी मसाला और गरम मसाला जैसे अन्य उत्पादों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. मामले की शुरुआत एक उपभोक्ता की शिकायत से पैकेट में मिलने वाले खाने-पीने के सामान को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. अगर किसी पैकेज्ड फूड में चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट तय सीमा से ज्यादा हुआ, तो उसके पैकेट के सामने एक बड़ा लाल चेतावनी निशान लगाया जा सकता है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इस नए लेबलिंग सिस्टम का प्रस्ताव रखा है. पैकेट के सामने लाल रंग का हेक्सागोन यानी छह कोनों वाला निशान लगाया जाएगा.

ग्राहक ने एक ब्रांड की हींग की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद एफएसएसएआई ने बाजार में उपलब्ध प्रमुख हींग ब्रांड्स की जांच शुरू की. जांच के दौरान एवरेस्ट और लालजी गोधू की कम्पाउंडेड हींग के सैंपल लिए गए. मुंबई स्थित दोनों कंपनियों की सेंट्रल लाइसेंस वाली यूनिट्स से सैंपल लेकर लैब में जांच कराई गई. नियमों के मुताबिक कम्पाउंडेड हींग में असली हींग के साथ गोंद, स्टार्च और आटे का मिश्रण किया जाता है. इसमें कम से कम 5% अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट होना जरूरी होता है.

यह कुछ हद तक' स्टॉप साइन' जैसा दिखाई देगा, इसका मकसद यह है कि ग्राहक पैकेट खोलने या सामान खरीदने से पहले ही आसानी से समझ सके कि उसमें चीनी, नमक या फैट की मात्रा ज्यादा है. अगर किसी प्रोडक्ट में इन चीजों की मात्रा तय सीमा से अधिक होती है, तो पैकेट पर बड़े और साफ अक्षरों में 'हाई शुगर', 'हाई साल्ट' या 'हाई फेट' लिखा जाएगा, यह जानकारी पैकेट के आगे वाले हिस्से पर प्रमुखता से दिखाई देगी. इसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉन्ट न्यूट्रिशन टेबल में दी गई जानकारी के फॉन्ट से कम से कम एक पॉइंट बड़ा रखना होगा.

बदलेगा हथकरघा क्षेत्र का भविष्य

सूती धागे का निर्यात नियंत्रित करने की मांग

कपड़ा निर्यातकों ने वाणिज्य मंत्री को पत्र लिखकर की अपील

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 30 अगस्त कपड़ा निर्यातकों ने सूती धागे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और भारतीय कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए इसके निर्यात को नियंत्रित करने की मांग की है.

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए. शक्तिवेल ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस दिशा में तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि आपूर्ति संबंधी दिक्कतों के कारण कच्चे कपास और सूती धागे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जिनिंग मिलों के पास कपास का सीमित भंडार है और आवक में कमी के चलते कपड़ा मिलें भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की नीलामी पर अधिक निर्भर हो रही हैं. निर्यातकों का कहना है कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त मात्रा में सूती धागा उपलब्ध कराने और लागत को नियंत्रित रखने के लिए निर्यात पर अस्थायी नियंत्रण जरूरी है.

एचडीएफसी बैंक सीईओ जगदीशन छोड़ेंगे पद

मुंबई. निजी क्षेत्र के प्रमुख ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) शशिधर जगदीशन ने पद छोड़ने का फैसला किया है और निदेशक मंडल को पुनर्नियुक्ति की मांग नहीं करने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है. जगदीशन का मौजूदा कार्यकाल इस साल 26 अक्टूबर को पूरा हो रहा है.

जीडीपी के आंकड़े देंगे बाजार को दिशा

निफ्टी-50 सूचकांक 76.35 अंक टूटकर 24,175.65 अंक पर आ गया

नवभारत न्यूज

मुंबई, 30 अगस्त घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और अन्य घरेलू आंकड़े बाजार को दिशा देंगे.

अगले सप्ताह सोमवार को जीडीपी के आंकड़े जारी होने हैं. इसके अलावा मंगलवार को विनिर्माण क्षेत्र के पीएमआई के आंकड़े और वाहनों की बिक्री के आंकड़े जारी होने हैं. सेवा क्षेत्र के पीएमआई के आंकड़े 03 सितंबर को जारी होंगे. ये सभी आंकड़े निवेशकों की धारणा को प्रभावित करेंगे. इनके अलावा, वैश्विक कारकों का असर भी बाजार पर रहेगा. गत सप्ताह प्रमुख सूचकांकों में मंगलवार और शुक्रवार को तेजी देखी गयी जबकि अन्य तीन दिन गिरावट के रहे. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 276.32 अंक (0.36 प्रतिशत) गिरकर सप्ताहांत पर 77,264.51 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 76.35 अंक यानी 0.31 प्रतिशत टूटकर 24,175.65 अंक पर आ गया. वृहत बाजार में तेजी देखी गयी. मिडकैप-50 सूचकांक में 0.47 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 0.51 प्रतिशत की साप्ताहिक तेजी रही. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 15 साप्ताहिक गिरावट में रहीं. भारती एयरटेल का शेयर सबसे अधिक 3.33 प्रतिशत टूट गया. एनटीपीसी का शेयर 2.51 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 2.48, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2.25, पावरग्रिड का 1.96 और बजाज फिनसर्व का 1.51 प्रतिशत फिसल गया।

गटाटा स्टील में 1.97 फीसदी, इंडिगो में 1.76, टाइटन में 1.67, एक्सिस बैंक में 1.42 और सन फार्मा में 1.01 फीसदी की साप्ताहिक तेजी रही. एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर 0.96 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स का 0.48, आईसीआईसीआई बैंक का 0.44, अल्ट्राटेक सीमेंट का 0.25, भारतीय स्टेट बैंक का 0.06 और इटरनल का 0.05 प्रतिशत ऊपर रहा.

समाचार विशेष

दो केंद्रीय मंत्रियों में आरक्षण पर महाभारत

चिराग ने मांगा इस्तीफा तो मांझी ने किया पलटवार!

नई दिल्ली, 30 अगस्त. केंद्र सरकार और बिहार की राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के भीतर ही घमासान मच गया है. केंद्र सरकार के दो कद्दावर बिहारी मंत्री लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान और हम पार्टी के प्रमुख और मोदी सरकार में मंत्री जीतनराम मांझी दलित आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' और वर्गीकरण के विचार को लेकर आमने-सामने आ गए हैं.

विवाद इतना बढ़ गया है कि चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से जीतनराम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन से केंद्रीय व राज्य मंत्री पद से इस्तीफा तक मांग लिया है. इसके जवाब में जीतन राम मांझी ने भी चिराग पासवान से इस्तीफा मांग लिया है.

यह पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले और उसके बाद उठी बहस से जुड़ा है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लागू करने की बात कही गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का यह तर्क है कि दलितों के भीतर भी कई ऐसी जातियां और वर्ग हैं जिन्हें दशकों बाद भी आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है.

एक-दूसरे पर करते रहे पलटवार

चिराग पासवान की मांग पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति व्यापक जनहित और गरीबों के कल्याण की बात को नहीं समझता है और इस तरह की बचकानी मांग करता है, तो उसे अपनी सोच पर विचार करना चाहिए. मांझी ने दो टूक शब्दों में कहा कि वे गरीबों के हक के लिए अपनी बात रखते रहेंगे और यह विभाजन समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में जरूरी है. एनडीए के भीतर दो सहयोगी दलों के इस तरह खुलेआम आमने-सामने आने से विपक्षी दलों को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है. हालांकि, देखना यह होगा कि इस अंदरूनी कलह को थामने के लिए बीजेपी हाईकमान क्या कदम उठाता है.

राम माधव कब तक करेंगे इंतजार?

नई दिल्ली, 30 अगस्त. भाजपा के संगठन पदाधिकारियों में सबसे दिलचस्प किस्सा राम माधव का है. राम माधव इन सभी महासचिवों में से सबसे पुराने हैं. वे पहले भी महासचिव रहे हैं और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रवक्ता थे. भाजपा के संगठन में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं. लेकिन संयोग से वे अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए हैं.

वे संघ की ओर से भाजपा की सक्रिय राजनीति में भेजे जाने के बाद भी चुनाव नहीं लड़े हैं. यह भी बहुत दिलचस्प है कि भाजपा की राजनीति में आने के बाद कई बार

उनको राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा रही है. इस बार फिर चर्चा है कि राम माधव को राज्यसभा भेजा जा सकता है. ध्यान रहे वे कई बार विवादों में रहे. जम्मू कश्मीर में पीडीपी और मुफ्ती परिवार के साथ तालमेल कराने में उनकी भूमिका मानी जाती है. पूर्वोत्तर में भी वे विवादों में घिरे. कुछ समय पहले उन्होंने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कह दिया था कि भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है. हालांकि बाद में इसके लिए माफी मांगी. तमाम विवादों के बावजूद कहा जाता है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय हैं. इसलिए इस बार शायद उनको भी राज्यसभा मिल जाए. नवंबर में ही वे भी राज्यसभा जाएंगे या उनके एक दो साल इंतजार करना पड़ेगा यह नहीं कहा जा सकता है.

एफपीआई ने अगस्त में 26,824 करोड़ लगाए

मुंबई. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले चार सप्ताह में 30 अगस्त तक भारतीय पूंजी बाजार में 26,824 करोड़ का शुद्ध निवेश किया है. शुद्ध निवेश बाजार में लगाई गयी पूंजी और बाजार से निकाली गयी पूंजी का अंतर है. यह लगातार तीसरा महीना है जब एफपीआई बाजार में लिवाल रहे हैं. इससे पहले जुलाई में उन्होंने 40,031 करोड़ और जून में उनका निवेश 4,669 करोड़ रुपये रहा था.

सपा-भाजपा के बीच विधानसभा चुनाव

अखिलेश यादव का बयान अहम क्यों, क्या बदल रही सियासत

विधानसभा चुनाव में सबकी जिम्मेदारी होगी तय

भाजपा की ओर से अभी किसी भी प्रकार के कोई संकेत नहीं

लखनऊ, 30 अगस्त. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे-धीरे गरमा रहा है. इस बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं।

भारतीय जनता पार्टी से लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम तक तैयारी को अंतिम रूप देता दिख रही हैं. पल्लवी पटेल की अपना दल कमेराबादी से लेकर एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी तैयारियों को तेज कर चुकी हैं.

अखिलेश यादव ने इस बीच बड़ा बयान दिया है. इसने राजनीतिक चर्चा को गरमाया है. अखिलेश यादव कहते दिख रहे हैं कि यूपी चुनाव 2027 में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही होगा।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही होगा. भाजपा सरकार को हटाने का मूड जनता बना चुकी है. सपा अध्यक्ष के सपा-भाजपा के बीच चुनाव होने के बयान ने प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. सवाल यह है कि क्या अभी से सपा अध्यक्ष अन्य दलों को खारिज करने की कोशिश में हैं? साथ ही, यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर सपा अध्यक्ष को इस प्रकार का बयान क्यों देना पड़ा? दरअसल, इसके पीछे की वजह विपक्षी दलों के बीच एकता का अभाव और भाजपा विरोधी वोट में दिख रहे संभावित बिखराव को माना जा रहा है. हाल के समय में प्रदेश के राजनीतिक मैदान में तमाम विपक्षी दलों ने अपनी तैयारियों को तेज किया है.

किस दल की क्या है तैयारी

यूपी चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी जमीन पर लगातार काम करती दिख रही है. बसपा अध्यक्ष मायावती ने चुनाव की कमान अपने हाथ में थामी है. अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतार दिया है. वह युवाओं और जेन-जी को सीधे तौर पर टारगेट करते दिख रहे हैं. साथ ही, जिलों में घूम-घूम कर उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं. बसपा अपने दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अगड़ा गठबंधन को मजबूत करने में जुटी है.

निकाय चुनाव **आधे युवा और महिलाएं, 150 को टिकट देना असली चुनौती**

जयपुर के 150 वार्डों में 2500 आवेदन

जयपुर, 30 अगस्त. नगर निगम चुनाव में भाजपा के टिकट के लिए बड़ी संख्या में आए आवेदनों ने पार्टी के भीतर सियासी हलचल बढ़ा दी. जयपुर के 150 वार्डों के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन मिलने के बाद अब दावेदारों की छंटनी शुरू हो गई. खास बात है कि इनमें 50 फीसदी महिलाएं और युवा आवेदक हैं.

महिलाओं और युवाओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी ने भाजपा के सामने टिकट वितरण को लेकर नए समीकरण खड़े कर दिए. माना जा रहा है कि पार्टी इस बार संगठन में सक्रियता के साथ नए चेहरों को मौका देने की रणनीति अपना सकती है. यदि टिकट वितरण में महिलाओं और युवाओं को अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिलता है तो जयपुर के कई वार्डों में अनुभवी चेहरों की जगह नई पीढ़ी चुनाव मैदान

में नजर आ सकती है. ऐसे में भाजपा का टिकट फॉर्मूला चुनावी नतीजों पर भी असर डाल सकता है.

इस बार भाजपा टिकट की दौड़ में महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी ने पार्टी के सामने नए समीकरण खड़े कर दिए हैं. जयपुर संभाग के निकाय प्रभारी और जयपुर नगर निगम चुनाव के पर्यवेक्षक प्रभुलाल सैनी ने बताया, करीब 50 फीसदी आवेदन महिलाओं और युवाओं के हैं. ये अच्छी बात है कि महिलाएं और युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है.

स्वभाव और जीतने की क्षमता पर टिकट

भाजपा ने उम्मीदवार चयन का फॉर्मूला साफ कर दिया है. जयपुर संभाग के निकाय प्रभारी और जयपुर नगर निगम चुनाव के पर्यवेक्षक प्रभुलाल सैनी बोले कि टिकट वितरण में किसी नेता के दबाव या प्रभाव को आधार नहीं बनाया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्याशी चयन दबाव, प्रभाव और अभाव के आधार पर नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और जीतने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा. सैनी का यह बयान टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे बड़े नेताओं के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है. उन्होंने कहा, पार्टी ऐसे दावेदारों को प्राथमिकता देगी, जिनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ हो. जनता के बीच स्वीकार्यता हो और जो चुनाव जीतकर पार्टी को मजबूत कर सकें.